# पंचदश

# बिहार विधान-सभा

## चतुर्दश सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

### वर्ग-3

बुधवार, तिथि 08 श्रावण 1936 (श0) / 30 जुलाई, 2014 (ई0)

**प्रश्नों की कुल संख्या 04**

| | | |
|---|---|---|
| (1) पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | .. .. | 01 |
| (2) पथ निर्माण विभाग | .. .. | 01 |
| (3) ग्रामीण विकास विभाग | .. .. | 01 |
| (4) जल संसाधन विभाग | .. .. | 01 |
| | कुल योग .. | 04 |

खर्च का औचित्य

'क'-26. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष, 2013-14 में राज्य योजना अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये प्रि-मैट्रिक/पोस्ट छात्रवृत्ति, प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, प्रावैधिक छात्रवृत्ति प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु 4,33,00,00,000 रुपये बजट में उपलब्ध किया गया था, जिसमें 50 प्रतिशत राशि खर्च नहीं किया जा सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष, 2010-11 में उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति 5,25,00,000 रु0, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति 9,75,00,000 रु0, प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति 20,00,00,000 रु0, प्रावैधिक छात्रवृत्ति 17,40,000 रु0, मुख्य मंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में मेधावृत्ति योजना 15,00,00,000 रु0, बजट में प्रावधान किया गया था, जिसमें 50 प्रतिशत राशि खर्च नहीं किया जा सका है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राशि खर्च नहीं करने का क्या औचित्य है ?

---

सड़क का निर्माण

35. डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर की पाँच कि0 मी0 लम्बी आशियाना-दीघा सड़क सघन आबादी के बीचोबीच गुजरती है तथा दो लाख लोगों को आवागमन सुविधा प्रदान करती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 21 करोड़ की लागत से उक्त सड़क के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष, 2006 में दी गयी तथा इसे वर्ष, 2008 में ही पूरा होना था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अभीतक सड़क का निर्माण पूर्ण नहीं होने का क्या औचित्य है ?

---

राशि प्रदान करना

36. डॉ0 अच्युतानंद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 मार्च, 2014 के अंक में छपी खबर "मनरेगा में काम नहीं, बेरोजगारी भत्ते की नौबत" के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में चल रहे मनरेगा कार्यक्रम के अधीन वर्ष, 2013-14 में 32 जिलों के 1854 पंचायतों द्वारा 146 करोड़ की राशि विभाग से माँग की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त राशि को पंचायतों को नहीं दिये जाने से मनरेगा का कार्यक्रम पिछले 6 महीने से अधिक समय से बाधित है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पंचायतों को राशि प्रदान करने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

नोट--'क' सदन द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2014 को स्थगित ।

दोषी पर कार्रवाई

37. डॉ0 अच्युतानंद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 जनवरी, 2014 के अंक में छपी खबर "करोड़ों का घपला, कागज पर ढोए पत्थर और बालू" के आलोक में क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष, 2013 में गंडक प्रोजेक्ट के अधीन मुख्य पश्चिमी गंडक नहर की मरम्मती के लिये 161 करोड़ की योजना का कार्य कराया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि निर्माण कार्य में स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया लेकिन बालू और पत्थर की ढुलाई कोइलवर और शेखपुरा से दिखायी गयी है और 50 करोड़ की राशि का दुरूपयोग किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 30 जुलाई, 2014 (ई0)।

हरे राम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

--------

बि0स0मु0 (एल0ए0), 82-डी0टी0पी0-450